हैल्थ-टुडे अक्टूबर-08 पेज-5

जब कभी किसी ने जिस उपाय से मति, कीर्ति, गतिएवं ऐश्वर्य प्राप्त किया वह सत्संग के प्रभाव से ही जानना चाहिए। लोक व वेद में उनको प्राप्त करने का दूसरा उपाय नहीं है।

देहरादून: बाबा रामदेव के पतंजलि
योग ट्रस्ट ने चमोली जिले के द्रोणगिरी पर्वत
से संजीवनी बूटी को खोज लेने का दावा
किया है। बाबा रामदेव ने इसे बड़ी उपलब्धि
बताते हुए आचार्य बालकृष्ण की टीम को
बधाई दी। आचार्य की टीम ने पहाड़ों पर
चढ़ाई करके इस बूटी को तलाशा है।
बालकृष्ण ने कहा कि संजीवनी बूटी में
चार तरह की बूटियां मृत संजीवनी, विषालय
कर्णी, स्वर्ण कर्णी और संधानी हैं। उत्तराखंड
के स्वास्थ्य मंत्री डा. रमेश पोखरियाल
निशंक ने कहा कि बिना जांच के संजीवनी
बूटी का पता लगा लेने का दावा करना
जल्दबाजी होगी। सवाल उठाया गया है कि
हिमालय में जब द्रोण पर्वत है ही नहीं तो
संजीवनी बूटी के पौधों को कैसे खोजा?

संजीवनी बूटी खोज
लेने का दावा

नई दिल्ली। जापान की प्रमुख दवा
कंपनी दाइची सैंक्यो को रैनबैक्सी का
अधिग्रहण करने के लिए सरकारी मंजूरी दे
दी है। इस डील से 21,560 करोड़ रुपए का
विदेशी निवेश आएगा। वित्त मंत्री पी
चिदंबरम ने आर्थिक मामलों की कैबिनेट
समिति (सीसीईए) की बैठक के बाद कहा
कि दाइची सैंक्यो रैनबैक्सी का अधिग्रहण
कर सकता है। जून में जापानी कंपनी ने
देश की सबसे बड़ी दवा निर्माता रैनबैक्सी
के शेयर खरीदने के लिए उसके प्रवर्तकों के
साथ करार किया था।

दाइची-रैनबैक्सी डील

को सरकार की म

ं

जूरी

टेस्ट ट्यूब पर
नई दिल्ली। टेस्ट ट्यूब जैसी कृत्रिम
प्रजनन तकनीकों को रेगुलेट करने के लिए
लाए गए बिल में चिकित्सा वैज्ञानिकों की
महत्वपूर्ण सिफारिशों की अनेदखी की गई
है कि प्रस्तावित कानून में मां-बच्चे के
स्वास्थ्य की चिंता की बजाय सैंकड़ों की
संख्या में खुल चुके
प्रजनन क्लिनिकों के
हिवतों की रक्षा की गई
है। देश में कृत्रिम
प्रजनन तकनीक
(असिस्टेड रीप्रोडक्शन
टेक्नोलॉजी) का
इतिहास 22 साल
पुराना है पर इन्हें
रेगुलेट करने की
कवायद पांच वर्ष पूर्व शुरू हुई। भारतीय
चिकित्सा अनुसंधान परिषद
(आईसीएमआर) ने पहले एआरटी
क्लिनिकों को रेगुलेट करने के लिए
गाइडलाइन तैयार की जिसे अब विधेयक में
तब्दील किया गया है। एआरटी रेगुलेशन
बिल-2008 में कृत्रिम तकनीक से महिला
के मां बनने की अधिकतम आयु सीमा नहीं
रखी गई है। पिछले साल अधिसूचित
गाइडलाइन में एआरटी अपनाने के लिए
21-30 साल की आयु निर्धारित की गई
थी। इसमें कहा गया था कि विवाह के दो
साल बाद भी यह संतानप्राप्ति नहीं होती है,
तो दंपति कृत्रिम तकनीक से बच्चा पैदा कर

सकते हैं। विधेयक में न्यूनतम आयु 21 साल
रखी गई, लेकिन अधिकतम का प्रावधान
नहीं है।
इसे वैज्ञानिकों का एक वर्ग ठीक नहीं
मानता। उनका कहना है कि मां बनने की
आदर्श उम्र 21 से 30 साल के बीच ही है।
लेकिन मौजूदा समय में
भी कई क्लिनिक
60-65 साल की
महिलाओं को संतान
सुख देने में कामयाब
हुए हैं। यह देखते हुए
वैज्ञानिकों के दूसरे वर्ग
का कहना है कि
टेक्नोलॉजी के लाभ के
मामले में उम्र की बंदिश
नहीं रखनी चाहिए। गाइडलाइन में
अविवाहित महिला को भी इस तकनीक का
लाभ देने की पैरवी की गई थी। लेकिन बाद
मे आपत्तियां उठने पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने
हस्तक्षेप कर यह प्रावधान खत्म कर दिया।
पर अब जो बिल बना है, उसमें फिर इसे
दूसरे रूप में शामिल किया गया है। इसमें
अकेली महिला या अकेले पुरुष को एआरटी
से संतान सुख हासिल करने की अनुमति है।
उसमें अविवाहित, तलाकशुदा या
विधवा-विधुर जैसी परिस्थितियों का जिक्र
नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि यह
प्रावधान अविवाहित लोगों को भी संतान पाने
का अधिकार देगा।

सिफारिशों की अनदेखी

स्टॉकहोम। जर्मनी के हैराल्ड जर
हॉसन और फ्रेंच रिसर्चर फ्रेंकोइज
बैरे-सिनॉसी और लक मौटेग्नाइर को
चिकित्सा के क्षेत्र में 2008 का पुरस्कार दिया
जाएगा। उन्हें एड्स वायरस की जानकारी
और गर्भाशय के कैंसर में वायरस की
भूमिका के लिए यह सम्मान दिया जा
रहा है।
बैरे-सिनॉसी और मौंटेग्नाइर ने ह्मूमन
इम्यूनो डेफिसिएंसी वायरस या एचआईवी
की स्टडी और जर हॉसन को गर्भाशय के
कैंसर के लिए जिम्मेदार पैपिलोमा वायरसों
की खोज की है। महिलाओं में गर्भाशय का
कैंसर बहुत आम है। जर्मन वैज्ञानिक को
प्राइज की राशि 14 लाख डॉलर का आधा
और दोनों फ्रेंच वैज्ञानिकों को बाकी राशि
का आधा-आधा मिलेगा। नोबल असेंबली ने
बयान में कहा कि बैरे-सिनॉसी और
मौंटेग्नाइर की खोज एड्स को समझने और

उसका इलाज खोजने की दिशा में बहुत
अहम साबित हुई। इन दोनों ने 80 के दशक
में एचआईवी-1 के जीनोम का क्लोन तैयार
किया था। इससे पता चला कि यह वायरस
कैसे अपने शिकार को संक्रमित करता है।
इनकी खोज से ही एड्स मरीजों के खून की
जांच मुमकिन हो सकी।
असेंबली ने कहा, जर हॉसन ने कैंसर
के लिए जिम्मेदार ह्मूमन पैपिलोमा वायरस या
ए चपीवी और गर्भाशय के कैंसर में उनकी
भूमिका को उजागर किया। इससे एचपीवी
के संक्रमण के तरीके की बेहतर जानकारी
मिली है। इसी के आधार पर इनके खिलाफ
वैक्सीन डिवेलप की जा रही हैं। स्वीडन के
वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की वसीयत के
आधार पर यह पुरस्कार स्थापित किए गए हैं।
यह पुरस्कार नोबल की पुण्यतिथि पर 10
दिसंबर को स्टॉकहोम और ओस्लो में दिए
जाते हैं।

एचआईवी पर स्टडी ने दिलवाया नोबल अवॉर्ड

नई दिल्ली। गत दिनों दिल्ली के
होटल दी कनाट में हरियाणा फार्मास्यूटिकल
मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की एक बैठक
आयोजित हुई। इस बैठक में निर्माताओं को
कार्य में आ रही परेशानियों को दूर करने पर
विचार विमर्श किया गया। वहीं ड्रग कन्ट्रोल
कार्यालय में रूके कार्यों को करवाने हेतू एक

हरियाणा दवा निर्माण

एसोसिएशन की बैठक आयोजित
कमेटी के गठन पर सहमति बनी। इसके
अलावा एनपीपीए एवं डीपीसीओ के मुद्दे पर
भी चर्चा की गई।
इसके अलावा आगामी दो वर्षों हेतू पुनः
श्री पी के गुप्ता व श्री टी.सी. कंसल को
प्रधान व महासचिव पद की जिम्मेवारी सौंप
दी गई।

चंडीगढ़ (हैल्थ टुडे एक्सक्लुसिव): पंजाब में वर्षों से
चिकित्सा कार्य कर रहे अन्य राज्यों से पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत चिकित्सकों हेतु राज्य सरकार जल्द ही रजिस्ट्रेशन आरंभ कर सकती है।
इस रजिस्ट्रेशन के तरीके को अमली जामा पहनाने हेतु
सरकार द्वारा बाकायदा एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो कि सरकार को अपनी सिफारिश करेगी कि इन चिकित्सकों को रजिस्ट्रेशन अथवा प्रमाण पत्र देने का स्वरूप क्या होना चाहिए। इस पांच सदस्यीय कमेटी में पंजाब आयुर्वेदिक बोर्ड के रजिस्ट्रार डा. संजीव गोयल, डा. रमेश बाली, डा. सुमन सूद, डा. बेदी एवं डा. शर्मा को शामिल किया
गया है। जानकार सूत्रों के अनुसार इस कमेटी ने इस मुद्दे पर

प

ं

जाब में श

ुरू होगा
रजिस्टन्न्ेशन, कमेटी गठित

विभिन्न चिकित्सक संगठनों से विमर्श करना आरंभ कर दिया है। इस
मुद्दे पर जहां कुछ अवधि का कोर्स करवाए जाने की बात सामने आ
रही है वहीं अनुभव के आधार पर प्रमाण पत्र दिए जाने का विचार भी
सामने आ रहा है।
इस आशय की पुष्टि स्वयं मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पंजाब
मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल के समक्ष नवांशहर में कर चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य रहे डा. एचएस राणू ने हैल्थ टुडे को बताया कि बकायदा मुख्यमंत्री महोदय स्वयं चाहते हैं कि प्रदेश के हजारों चिकित्सकों को उनके रोजगार की गारंटी मिले एवं उन्हें प्रदेश से ही कोई प्रमाण पत्र आदि प्रदान कर चिकित्सा कार्य की अनुमति दे दी जाए। दूसरी ओर नीमा संगठन ने इस कार्रवाई का विरोध करना अभी से शुरू कर दिया है।

नई दिल्ली। दवाओं के बढ़ते दामों
से लोगों को निजात दिलाने को केन्द्र
सरकार ने अपने ड्रग रिटेल आउटलेट
खोलने की योजना बनाई है। ये आउटलेट
देश के हर जिले में खुलेंगे। योजना को
फाइनल शेप में पहुंचाने में अभी वक्त
लगेगा।
मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्युटिकल के
जॉइंट सेक्रटरी गुरदयाल सिंह संधू का
कहना है कि योजना का पूरा स्ट्रक्चर तैयार
है। इसके मुताबिक सबसे पहले देश के 600
जिलों में आउटलेट खोले जाएंगे। इन
जिलों के नामों पर अभी चर्चा चल रही है।
उनका कहना है कि इससे आम लोगों तक
बहुत ही कम बेनिफिट पर सही दवाएं
उपलब्ध कराई जा सकेंगी। क्योंकि
फिलहाल कई चरणों से होकर दूर दराज
इलाकों तक दवाएं पहुंचने में कई तरह के
टैक्स लग जाते हैं। पिछड़े इलाकें में कई
बार नकली दवाएं भी बिक रही होती हैं।
गवर्नमेंट आउटलेट खुलने से लोगों को इन
दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
उनका कहना है कि इसके लिए
भागीदारी योजना के तहत भी काम किया
जा सकता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट, ब्रैंडेड

हर जिले में सस्ते दवाघर खोलेगी सरकार
फार्मास्युटिकल कंपनियों और एनजीओ की
मदद भी ली जाएगी। संधू ने बताया कि
योजना से संबंधित सभी लोगों की बैठक
होगी और अगले दो महीनों के भीतर इस
योजना पर काम शुरू हो जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में
भारत में दवाओं की कीमत में एक से दो
फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है। नैशनल
फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी
(एनपीपीए) कंपनियों को दवाओं की
पैकेजिंग और प्रॉसेसिंग कॉस्ट रिटेल प्राइस
में जोड़ने की अनुमति देने की योजना बना
रहा है। अथॉरिटी का पैनल जल्द ही
कन्वर्जन, पैकेजिंग और पैकिंग मटीरियल
की कॉस्ट को रिवाइज करने वाला है। 6
महीने के मार्किट अनैलिसिस के बाद पिछले
सप्ताह इसके लिए नॉर्म्स डिसाइड किए गए
हैं। रिवाइज्ड प्राइस का असर दवाओं के 3 5
हजार करोड़ के घरेलू मार्किट के तहत
बिकने वाली सभी दवाओं पर पड़ेगा।
गौरतलब है कि पिछले दिनों देश भर
में कई जगह नकली दवाएं पकड़ी जाने के
बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
(आईएमए) जैसे संगठनों ने केन्द्र सरकार से
देश भर में दवाओं के सरकारी रिटेल

आउटलेट खोलने की मांग की थी, ताकि
लोगों को सही दवाएं मिल सकें। आईएमए
की स्टडी के मुताबिक देशभर में बिकने
वाली लगभग 35 फीसदी दवाएं नकली हैं।
इसकी वजह से पैसे खर्च करने के बावजूद
लोगों को इलाज का कोई फायदा नहीं होता
है। ऐसे में केन्द्र सरकार की नई योजना
आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित
हो सकती है।

आवश्यकता है

ज्योति अस्पताल व टन्न्ामा सैन्टर

पटौदी रोड,
फरूख नगर

Cont. : 9813434018, 9416114606, 0124-2375198

टन्न्ेन्ड नर्सिंग स्टाफ - 3 टन्न्ेन्ड वार्ड ब्वाय - 3
टन्न्ेन्ड व्ण्ज्ण् ।ेेपेजंदज - 1
डण्ठण्ठण्ैण् . 1

ठण्।ण्डण्ैण् .1

Lab Technician - 2

ये कैसा देश है मेरा

फरीदकोट (ब्यूरो चीफ)। मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण हेतू मृत देह है के लिए भटकने वाले कॉलेज प्रबन्धन की बेशर्मी तब सामने आई जब एक जागरूक व्यक्ति स्व. श्री जगीर सिंह ने अपनी देह को मेडिकल कॉलेज को दान की इच्छा जीते जी व्यक्त की थी, उनकी इच्छा अनुरूप मृत्यु उपरान्त उनके परिवार वाले उनकी देह को मेडिकल कॉलेज फरीदकोट लेकर गए, ताकि उस मृत देह से मेडिकल के विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। किन्तु यहां का सिस्टम देख सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज ने परिवार वालों को मृत देह के साथ सांय तक इधर से उधर चक्कर कटवाते रहे। सांय को मिडिया के पहुंचने पर आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज प्रबन्धन ने यह मृत देह ली। एक तरफ तो मेडिकल कॉलेज प्रशिक्षण हेतू मृत देह की कमी का रोना रोते हैं वहीं जब कोई जागरूक परिवार ऐसा करने की हिम्मत जुटाता है तो मेडिकल कॉलेज का होनहार प्रबंधन पूरे दिन इधर से उधर मृत देह के साथ भटकने को मजबूर कर देता है।